झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

द्वितीय अपील सं. 153/2020

जगदीश महतो, उम्र 52 वर्ष, पिता स्व. सोना राम महतो, निवासी ग्राम-सहरपुरा, डाकघर कुसुंडा, थाना- पुटकी, जिला-धनबाद, वर्तमान में निवासी गोधर कुर्मिडी बस्ती, डाकघर केन्दुआडीह, थाना- केन्दुआडीह, जिला-धनबाद

.... प्रतिवादी/उत्तरदाता/अपीलकर्ता

बनाम

मनी राम महतो, पिता स्व. छुटू महतो, निवासी ग्राम-गोधर, डाकघर- केन्दुआडीह, थाना- केन्दुआडीह, जिला-धनबाद

.... वादी/अपीलकर्ता/उत्तरदाता

उपस्थित

माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

अपीलकर्ता के लिए : श्री ओम प्रकाश सिंह, अधिवक्ता

श्री एस.एन. दास, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : श्री रामचंद्र साहू, अधिवक्ता

श्री सुधीर कुमार शर्मा, अधिवक्ता

<u>न्यायादेश</u>

<u>सी.ए.वी. 30/11/2023</u> को सुनाया गया, 29/02/2024 को घोषित किया गया

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

1. यह द्वितीय अपील सिविल अपील सं. 97/2018 में पारित निर्णय और डिक्री को निरस्त करने के लिए दायर की गई है, जिसमें प्रथम अपील अदालत ने अपने 18.02.2020 के निर्णय और 25.02.2020 की डिक्री के द्वारा 14.06.2018 के निर्णय और 26.06.2018 की डिक्री को पलट दिया था।
2. मामले का तथ्यात्मक आधार यह है कि मठजा गोधर के खाता सं. 31, प्लॉट सं. 1326, क्षेत्रफल 13 डिसमिल की भूमि का नाम सी.एस. रिकॉर्ड ऑफ राइट में भादु महतो के नाम दर्ज था। भादु महतो ने उक्त भूमि पर मकान का निर्माण किया और अपनी मृत्यु तक अपने परिवार के साथ वहाँ रहने लगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके दो पुत्र बनेश्वर महतो और छुटू महतो ने उक्त भूमि को संयुक्त रूप से विरासत में लिया और विवादित प्लॉट और परिसर में रहते रहे। बाद में बनेश्वर महतो और छुटू महतो ने अपनी भूमि और मकान को आधे-आधे हिस्सों में बाँट लिया, यानी 6 ½ डिसमिल भूमि। यह भी आरोप है कि छुटू महतो का निधन वर्ष 1945 में हुआ, उनके पीछे उनकी विधवा रशु महताइन और तीन पुत्र बिरबल महतो, हीरालाल महतो, मनीराम महतो और तीन पुत्रियाँ मंजवा महताइन, संजवा महताइन और कुंती महताइन उनके कानूनी वारिस के रूप में रह गए। बाद में, वर्ष 1949 में रशु महताइन की मृत्यु हो गई और सभी तीन पुत्र संयुक्त कब्जे में छुटू महतो की भूमि पर बने रहे। तीनों पुत्रियाँ मंजवा महताइन, संजवा महताइन और कुंती महताइन ने छुटू महतो की भूमि पर कोई अधिकार नहीं प्राप्त किया क्योंकि वे अपने पति के साथ दूसरे गाँव में रह रही थीं। आरोप है कि बिरबल महतो और हीरालाल महतो की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु हो गई और उनके अधिकार मनीराम महतो के पास आ गए जो अकेले ही शेड्यूल (ए) में उल्लिखित भूमि और मकान में कब्जे में रहे।
3. प्रतिवादी जगदीश महतो, जो कुंती महताइन के पुत्र हैं, कुंती महताइन की मृत्यु के बाद वादी (मामा) के घर में पले-बढ़े और जब वे वयस्क हो गए, तो उन्हें विवादित परिसर में एक कमरे में रहने की अनुमति दी गई, और प्रतिवादी का कब्जा प्रारंभ से ही स्वीकृत रूप में था और उन्हें शेड्यूल "बी" में वर्णित संपत्ति पर कोई अधिकार, शीर्षक और हित प्राप्त नहीं हुआ।

4. अप्रैल, 2006 में, प्रतिवादी ने शेड्यूल "बी" में वर्णित कमरे और मकान पर अपना हित दावा करना शुरू किया और बिना वादी की सहमति के आवासीय उद्देश्य के लिए दिए गए उक्त परिसर के पुनर्निर्माण के लिए टाइल्स को हटा दिया। इस घटना ने वादी के शीर्षक पर संदेह पैदा किया, इसलिए अधिकार, शीर्षक और हित की घोषणा के साथ-साथ कब्जा वसूली के लिए मुकदमा दायर किया गया, जिसे टाइटल सूट सं. 76/2006 के रूप में पंजीकृत किया गया।
5. दूसरी ओर, प्रतिवादी का मामला है कि भादु महतो की संपत्ति छुटू महतो और बनेश्वर महतो के पास गई, जो परिवारिक समझौते के अनुसार अलग-अलग संपत्ति में रह रहे थे। छुटू महतो प्लॉट सं. 1326 क्षेत्रफल 6 ½ डिसमिल में आधे हिस्से के मकान में रह रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु वर्ष 1959 में हुई, न कि वर्ष 1945 में जैसा कि वादी ने दावा किया है। छुटू महतो की पत्नी का निधन 1976-77 में हुआ, न कि वर्ष 1949 में जैसा कि वादी ने दावा किया है।
6. इस प्रकार, चुटू महतो और उनकी पत्नी रासुआ महताइन की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने के बाद हुई, इसलिए चुटू महतो की सभी पुत्रियाँ, अर्थात् मंजवा महताइन, संजवा महताइन और कुंती महताइन ने चुटू महतो की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किया, जिसमें शेड्यूल "ए" में वर्णित संपत्ति भी शामिल है, अपने भाइयों के साथ। चूंकि बिरबल महतो और हीरालाल महतो की कोई संतान नहीं थी, उनके हिस्से की संपत्ति भी जीवित उत्तराधिकारियों और परिवार के सदस्य, जैसे मनीराम महतो और उनकी जीवित बहनों, जिसमें प्रतिवादी की मां भी शामिल हैं, के पास आई। यह पूरी तरह से गलत है कि केवल मनीराम महतो ने चुटू महतो द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किया।

   प्रतिवादी की मां की मृत्यु जब वह नाबालिग था, और तब वह वादी के घर में अपने अधिकार के रूप में रह रहा था, न कि वादी द्वारा दी गई स्वीकृत कब्जे के आधार पर जैसा कि आरोपित किया गया है। इसलिए, वादी के पास कोई कारण या अधिकार नहीं है कि वह किसी राहत का दावा करे, और मुकदमा खारिज करने योग्य है।
7. पक्षों की याचिका के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दे निर्णय के लिए निर्धारित किए गए थे:

   (1) क्या मुकदमा वर्तमान रूप में चलाया जा सकता है?

(2) क्या वादी के पास कोई वैध कारण है?

(3) क्या मुकदमा माफ, रोकथाम और स्वीकार्यता के आधार पर बाधित है?

(4) क्या मुकदमा पक्षों के गैर-शामिल और गलत-शामिल के आधार पर बाधित है?

(5) क्या विवादित संपत्ति वादी और प्रतिवादी की संयुक्त संपत्ति है?

(6) क्या वादी को विवादित संपत्ति पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित है?

(7) क्या वादी को किसी राहत या राहतों का अधिकार है जैसा कि दावा किया गया है?

8. अपने मामले को साबित करने के लिए वादी ने 6 मौखिक गवाहों की गवाही दी और निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए:

प्रस्तावना-1: मूल बिक्री दस्तावेज संख्या 6851 दिनांक 22.06.1950

प्रस्तावना-2: किराया रसीद दिनांक 20.06.2006

प्रस्तावना-3: खाता संख्या 31 के खतियान की प्रमाणित प्रति, मउजा गोधर

प्रस्तावना-4: मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तीन मौखिक गवाहों की गवाही दी: जगदीश महतो (डी.डब्ल्यू.-1), जगदीश चंद्र महतो (डी.डब्ल्यू.-2) और गंगाधर महतो (डी.डब्ल्यू.-3), और प्रतिवादी ने मतदाता सूचियों की प्रति प्रस्तावना-ए और प्रस्तावना-ए/1 को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया।

10. निचली अदालत ने यह मुद्दा तय करते हुए कि चुटू महतो की मृत्यु 1945 में हुई या 1959 में, देखा कि प्रस्तावना-1 बिक्री दस्तावेज संख्या 6851 दिनांक 22.06.1950 एक बिरू महतो द्वारा निष्पादित किया गया प्रतीत होता है, जो स्व. चुटू महतो का पुत्र है। प्रतिवादी ने इस बिक्री दस्तावेज पर आपत्ति की क्योंकि चुटू महतो का पुत्र बिरबल महतो था, बिरू महतो नहीं। वादी ने यह भी आरोपित किया कि उसे उक्त बिक्री दस्तावेज अपने पिता चुटू महतो से उनकी मृत्यु के

बाद प्राप्त हुआ, जो वादी के संस्करण पर संदेह उत्पन्न करता है कि यदि उसके पिता की मृत्यु 1945 में हुई, तो यह दस्तावेज कैसे उसके पिता के पास था। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया क्योंकि वादी अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहा।

11. निचली अदालत ने मुद्दा सं. 5 और 6 को एक साथ निर्णय के लिए लिया और पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर विश्लेषण करके यह निष्कर्ष निकाला कि वादी अपने आरोपों को ठोस साक्ष्य के माध्यम से साबित करने में विफल रहा कि चुटू महतो की मृत्यु 1945 में हुई और 1959 में नहीं। इसी प्रकार, वादी ने संपत्ति के विभाजन को साबित करने में भी विफल रहा, बल्कि यह वादी और प्रतिवादी की संयुक्त परिवार की संपत्ति थी। तदनुसार, मुख्य मुद्दों पर निर्णय के आधार पर, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया।

12. पहले अपीलीय अदालत ने दो बुनियादी बिंदुओं को निर्णय के लिए तैयार किया: "क्या वादी/अपीलकर्ता को शेड्यूल "ए" में वर्णित विवादित भूमि पर कोई अधिकार, शीर्षक और हित प्राप्त है?" और "क्या वादी को शेड्यूल "बी" संपत्ति पर कब्जा वसूली का अधिकार है?"

13. अपीलीय अदालत ने यह प्रश्न उठाया कि 1956 के बाद चुटू महतो की मृत्यु के बाद क्या वादी ने केवल शेड्यूल – ए भूमि पर एकमात्र अधिकार प्राप्त किया या उसने अपने तीन बहनों के साथ, जिसमें प्रतिवादी की मां भी शामिल है, संयुक्त रूप से उत्तराधिकार प्राप्त किया। अपीलीय अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 की व्यवस्था पर भरोसा किया:

> **<u>धारा 23 विशेष प्रावधान निवास घरों के संबंध में</u>-** जहां एक हिंदू अविवाहित ने अपने जीवित पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों को वर्ग । में निर्दिष्ट किया है और उसकी संपत्ति में एक निवास घर पूरी तरह से उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अधिकृत है, तो इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, किसी भी महिला उत्तराधिकारी का निवास घर के विभाजन का दावा तब तक नहीं उठेगा जब तक पुरुष उत्तराधिकारी अपने-अपने हिस्से को विभाजित नहीं कर लेते; <u>लेकिन महिला उत्तराधिकारी को निवास का अधिकार प्राप्त होगा:</u>

ध्यान दें कि जहां ऐसी महिला उत्तराधिकारी एक बेटी है, तो उसे निवास घर में निवास का अधिकार केवल तभी प्राप्त होगा जब वह अविवाहित हो या पति द्वारा त्याग दी गई हो या पति से अलग हो या विधवा हो।

14. उपर्युक्त संदर्भ में, अपीलीय अदालत ने यह पाया कि विवादित संपत्ति एक आवासीय घर है और प्रतिवादी की मां, जो चुटू महतो की पुत्री थीं, की मृत्यु 1985 में हुई थी और उन्होंने कभी भी विवादित घर में निवास नहीं किया।

यह भी देखा गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 को संशोधित अधिनियम, 2005 द्वारा हटा दिया गया था, लेकिन इससे पहले प्रतिवादी की मां, कांति महताइन ने विवादित संपत्ति पर अधिकार के अनुसार निवास किया है, यह प्रतिवादी द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि उसकी मां त्यागी गई थी, अलग हुई थी या तलाकशुदा थी। तदनुसार, प्रतिवादी की मां कभी भी विवादित भूमि में साझेदार नहीं थी और न ही उसे विवादित भूमि पर निवास का अधिकार था। यह भी तथ्य है कि वादी के दो भाई बिना संतान के और बिना विधवा के मर गए थे। इसलिए, वादी ने शेड्यूल-ए में वर्णित पूरी 6 ½ डिसमल भूमि पर अधिकार, शीर्षक और हित प्राप्त किया है और प्रतिवादी को उक्त शेड्यूल ए और बी भूमि पर कोई अधिकार, शीर्षक और हित नहीं है। तदनुसार, दोनों बिंदुओं का निर्णय वादी/अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया और वादी का मुकदमा परस्पर लड़ा गया।

15. विवादित निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर अपील की है:

(i) क्या प्रथम अपीलीय अदालत ने 18.02.2020 के अपने निर्णय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 पर भरोसा करके गंभीर अवैधता की है और मुकदमे के संबंध में, जिसका कारण 15.04.2006 और इसके बाद की तारीखों पर उत्पन्न हुआ था, जबकि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 23 को हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की धारा 4 द्वारा 09.09.2005 से हटा दिया गया था?

(ii) क्या प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा प्राप्त तथ्यों की निष्कर्ष निराधार है?

16. अपीलकर्ता के वकील ने विवादित निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए निम्नलिखित तर्क किए:

(i) वादी ने यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके पिता हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले मृत्यु हो गए थे, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अनुसार, 2005 में संशोधित और प्रतिस्थापित किया गया, प्रतिवादी की मां, कांति देवी, जो चुटू महतो की पुत्री हैं, अपने मृत पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने के योग्य थीं और अपीलकर्ता/प्रतिवादी भी विवादित संपत्ति में अधिकार प्राप्त करते हैं।

(ii) निचली अदालत ने सही ढंग से इस मामले में शामिल मुद्दे को समझा और वादी के मुकदमे को खारिज कर दिया, लेकिन अपीलीय अदालत ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 और 23 के प्रावधानों की गलत व्याख्या की, जबकि धारा 23 को भी संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा हटा दिया गया है।

(iii) अपीलीय अदालत ने यह नहीं समझा कि हीरालाल महतो वादी के भाई थे जिन्होंने प्रतिवादी/अपीलकर्ता जगदीश महतो को उसकी मां, कांति महताइन की मृत्यु के बाद 15 साल की उम्र में अपने पास ले लिया। अपीलकर्ता ने हीरालाल महतो का अंतिम संस्कार बेटे की तरह किया और शेड्यूल बी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा, चुटू महतो की पुत्री के बेटे के रूप में स्वतंत्र अधिकार से।

(iv) अपीलकर्ता की उम्र 2006 में लगभग 38 वर्ष थी और उसने विवादित संपत्ति पर अधिकार, शीर्षक और हित प्राप्त किया। वादी का शेड्यूल बी संपत्ति पर विशेष अधिकार का दावा कानून के तहत उचित नहीं है।

17. उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री को रद्द करने योग्य माना जाता है और निचली अदालत द्वारा पारित डिक्री को मान्यता दी जानी चाहिए और इस अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए।

18. ***इसके विपरीत,*** वादी/प्रतिवादी के वकील ने अपीलकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता चुटू महतो का पुत्री का बेटा है और विवादित संपत्ति एक आवासीय घर है, इसलिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 या धारा 23 के संशोधित प्रावधानों के दृष्टिकोण से प्रतिवादी/अपीलकर्ता को विवादित संपत्ति में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।
19. प्रतिवादी/अपीलकर्ता को अपने स्वयं के अधिकार पर विवादित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त करने का कोई हक नहीं था, इसलिए प्रथम अपीलीय अदालत की दृष्टिकोण कानूनी रूप से उचित है और इस अपील के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, और यह योग्यता से खाली है, इसलिए इसे खारिज करने योग्य है।
20. उपरोक्त महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर निर्णय देने से पहले, संबंधित मुद्दों के उचित निपटारे के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों पर चर्चा करना लाभकारी होगा।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की लागू होने से पहले, भारत में मुख्यतः दो हिंदू विधि स्कूल थे:- दायभाग: यह पूर्वी भारत, जैसे बंगाल और इसके आस-पास के क्षेत्रों में प्रचलित था, और मिताक्षरा: यह भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित था। मिताक्षरा स्कूल के तहत, एक संयुक्त परिवार में महिलाओं के पास केवल रखरखाव/जीविका का अधिकार था, लेकिन संपत्ति में उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं था। हिंदू संयुक्त परिवार की नींव एक सामान्य पुरुष पूर्वज पर आधारित थी और परिवार की संपत्तियाँ संदायादता संपत्ति के रूप में रखी जाती थीं, जहां पुरुष सदस्य जन्म के अधिकार से संपत्ति के अधिकार रखते थे। संदायादता संपत्ति में पुरुष सदस्य की मृत्यु पर संपत्ति उत्तरजीविता के आधार पर हस्तांतरण होती थी। मिताक्षरा स्कूल के तहत कोई महिला संदायादता की सदस्य नहीं होती, हालांकि वह संयुक्त हिंदू परिवार की सदस्य हो सकती है। संदायादता सामान्यतः चार पीढ़ियों तक सीमित होती है, यानी सामान्य पूर्वज (सहभागी), उनका बेटा, पोता, और परपोता।

21. दायभाग स्कूल में, बेटियाँ भी अपने भाइयों के साथ समान हिस्से की हकदार होती थीं। दायभाग स्कूल में, संपत्ति उत्तराधिकार द्वारा स्थानांतरित की जाती है और उत्तरजीविता द्वारा नहीं। दायभाग स्कूल में संदायादता संपत्ति का कोई अवधारणा नहीं था और एक संयुक्त हिंदू परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी/अपनी

स्वतंत्र अधिकार में संपत्ति को रखने और उसे दान या वसीयत के माध्यम से निपटाने के योग्य था। इसलिए, दायभाग स्कूल में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे।

22. महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार से संबंधित पहली विधायी पहल 1929 में की गई थी, जिसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1929 कहा गया। इस अधिनियम ने तीन महिलाओं के उत्तराधिकार के अधिकार प्रदान किए - बेटे की बेटियाँ, बेटी की बेटियाँ, और बहनें। इसके माध्यम से उत्तरजीविता के विशेष नियम पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला अधिनियम हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार अधिनियम, 1937 था। इस अधिनियम ने विधवा को मृत पति की संपत्ति में बेटे के साथ समान हिस्सा पाने का अधिकार प्रदान किया, लेकिन विधवा को संपत्ति पर जीवनकाल के दौरान केवल सीमित संपत्ति (जीवनकाल संपत्ति) का अधिकार था और वह संपत्ति को अपने जीवनकाल में निपटा नहीं सकती थी।

23. 1950 में, संविधान बनाते समय, संविधान के अनुच्छेद 14, 15(2) (3) और 16 ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव की प्रथा को रोकने और महिलाओं की समानता को संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाने की कोशिश की। इस संवैधानिक उद्देश्य के अनुसार, संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (प्रारंभिक अधिनियम) को पारित किया। यह अधिनियम सभी हिंदुओं, जिसमें बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं, पर लागू होता है। इसने महिलाओं के लिए उत्तराधिकार के लिए एक समान और व्यापक विधि प्रस्तुत की और यह मिताक्षरा या दायभाग स्कूल के तहत आने वाले सभी हिंदुओं पर लागू होता है। हालांकि, प्रारंभिक अधिनियम की धारा 6 ने संदायादता संपत्ति के स्थानांतरण की भूमिका को उत्तरजीविता के आधार पर बनाए रखा, हालांकि इसने हिंदू पुरुष को अपनी संपत्ति, जिसमें संदायादता शेयर भी शामिल है, के संबंध में वसीयत का अधिकार प्रदान किया। पूर्ववर्ती धारा 6 (पूर्व संशोधित धारा 6) इस प्रकार थी:

> **धारा 6: संदायादता संपत्ति में हित का स्थानांतरण:**
>
> *"जब एक पुरुष हिंदू इस अधिनियम की प्रारंभिक तिथि के बाद मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु के समय उसके पास एक मिताक्षरा संदायादता संपत्ति में एक हित होता है, तो उसकी संपत्ति में हित उत्तरजीविता के आधार पर संदायादता के जीवित सदस्यों को स्थानांतरित हो जाएगा और इस अधिनियम के अनुसार नहीं होगा:*

प्रस्तावना: यदि मृतक के पास जीवित कोई महिला संबंधी है जो अनुसूची की किसी श्रेणी I में निर्दिष्ट है या ऐसी महिला संबंधी के माध्यम से दावा करने वाला कोई पुरुष संबंधी है, तो मिताक्षरा संदायादता संपत्ति में मृतक का हित वसीयत या उत्तराधिकार के आधार पर इस अधिनियम के तहत स्थानांतरित होगा और उत्तरजीविता के आधार पर नहीं होगा।"

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, हिंदू मिताक्षरा संदायादता का हित उस संपत्ति में हिस्से के रूप में माना जाएगा जो उसकी मृत्यु के ठीक पहले संपत्ति के विभाजन में उसे आवंटित किया जाता, चाहे वह विभाजन का दावा करने का अधिकार रखता हो या नहीं।

स्पष्टीकरण II.- इस धारा की प्रस्तावना में किसी भी बात को इस प्रकार नहीं समझा जाएगा कि जो व्यक्ति मृतक की मृत्यु के पहले संदायादता से अलग हो गया है या उसके किसी भी वारिस से अलग हो गया है, वह उत्तराधिकार पर एक हिस्से का दावा कर सके।

24. यह ध्यान देने योग्य है कि हिंदू कोड बिल ने हालांकि मिताक्षरा सहपरिवार व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के मुख्य अधिनियम की धारा 6 मिताक्षरा सहपरिवार संपत्ति को बनाए रखने की वकालत करती है। मूल रूप से, धारा 6 का प्रावधान यह है कि यदि सहपरिवार संपत्ति में विभाजन होता है, तो प्रत्येक पुरुष सहपरिवार सदस्य को उसका हिस्सा मिलेगा, और माँ तथा पत्नी/विधवा सहपरिवार सदस्य नहीं बनेंगी, लेकिन उन्हें सहपरिवार संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। लेकिन बेटी को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बेटी को केवल सहपरिवार सदस्य की मृत्यु पर, सहपरिवार संपत्ति में मृतक के हिस्से के काल्पनिक विभाजन से, उत्तराधिकारियों में से एक के रूप में हिस्सा मिलेगा।

25. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत के कानून आयोग ने मई 2000 की अपनी 174वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए सुधार की आवश्यकता है। आयोग ने सिफारिश की कि बेटी को जन्म के समय संदायादता बनाया जाए और उसे विभाजन या पुरुष संदायादता की मृत्यु पर हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार हो। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि विवाह के बाद की गई बेटियों को भी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी का

अधिकार दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने विवाह से पहले संदायादता का दर्जा प्राप्त किया है।

26. 20 दिसंबर, 2004 को हिंदू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, 2004 राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य मुख्य अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 6 में संशोधन करना और पूर्ववर्ती धारा 23 को हटाना था। "मुख्य अधिनियम" में संशोधन के लिए उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य इस प्रकार है:-

उद्देश्य और कारणों का बयान:

"हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 ने हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों को संशोधित और संहिताबद्ध किया और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्रदान किए, जो पहले अज्ञात थे। हालांकि, यह मिताक्षरा संदायादता के सदस्यों के विशेष अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करता, केवल कुछ मामलों में पुरुष के मृत्युपरांत हित की परिकल्पना के नियम प्रदान करता है। अधिनियम एक समान और व्यापक उत्तराधिकार प्रणाली प्रदान करता है और यह मिताक्षरा या दायभाग स्कूल या पूर्ववर्ती मुरू, मक्कट्टीम उर्फ अलीयस्तान्तन और नंबूदिरी कानूनों के तहत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होता है। यह अधिनियम हर व्यक्ति पर लागू होता है जो हिंदू धर्म का पालन करता है, जिसमें वीराशिव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी शामिल हैं; या बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी शामिल हैं; या अन्य व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म का पालन नहीं करते। यदि वसीयत की गई हो, तो यह अधिनियम लागू नहीं होता और मृतक का हित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होता है।"

धारा 6 पुरुष हिंदू के संदायादता संपत्ति में हित के स्थानांतरण की व्यवस्था करती है और संदायादता के बीच उत्तरजीविता के नियम को मान्यता देती है। मिताक्षरा संदायादता संपत्ति को बनाए रखना और इसमें महिलाओं को शामिल न करना, यह दर्शाता है कि महिलाएं अपनी पुरुष समकक्षों के समान पारिवारिक संपत्ति में उत्तराधिकार का दावा नहीं कर सकतीं। *यह कानून बेटी को संदायादता संपत्ति के स्वामित्व में शामिल न करके न केवल लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है, बल्कि इसके साथ संविधान द्वारा दिए गए समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है।*

27. महिलाओं के लिंग सामाजिक न्याय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने मिताक्षरा संदायादता संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार देने के लिए कानून में आवश्यक परिवर्तन किए हैं। केरल विधानमंडल ने केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975 को लागू किया है।

इसके साथ ही, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में धारा 6 में वर्णित भेदभाव को समाप्त करने का प्रस्ताव है, ताकि बेटियों को हिंदू मिताक्षरा संदायादता संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हो, जैसा कि बेटों को है। धारा 23 इस अधिनियम के अनुसार, एक महिला उत्तराधिकारी को संयुक्त परिवार द्वारा पूरी तरह से कब्जा किए गए एक आवासीय घर में विभाजन की मांग का अधिकार नहीं देती, जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी अपने हिस्से का निर्णय न ले लें। यह प्रस्तावित किया गया है कि इस धारा को समाप्त किया जाए, ताकि महिलाओं को नकारात्मक भेदभाव से मुक्त किया जा सके।

28. इसके बाद, 9 सितंबर, 2005 को, संशोधन अधिनियम, 2005 पारित हुआ, जो 09.09.2005 से प्रभावी हुआ, जिसके द्वारा मुख्य अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया, जो इस प्रकार है:

धारा 6 - सहपरिवार संपत्ति में हित का उत्तराधिकार: (1) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से, मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिंदू परिवार में, सहपरिवार सदस्य की बेटी-

(a) जन्म से ही अपने अधिकार में संदायादता बन जाएगी, जैसे कि पुत्र होता है;

(b) संदायादता संपत्ति में वही अधिकार प्राप्त करेगी जो उसे पुत्र के रूप में प्राप्त होते;

(c) उक्त सहपरिवार संपत्ति के संबंध में बेटी उसी प्रकार की देनदारियों के अधीन होगी जैसे कि एक पुत्र, और किसी भी हिंदू मिताक्षरा सहपरिवार सदस्य के संदर्भ में उसे सहपरिवार सदस्य की बेटी के संदर्भ में भी माना जाएगा।

इस उपधारा में निहित कोई भी बात उस संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण या परित्याग, जिसमें कोई विभाजन या वसीयत द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण शामिल है, जो 20 दिसंबर, 2004 से पहले हो चुका हो, को प्रभावित या अमान्य नहीं करेगी।

(2) जिस संपत्ति पर एक महिला हिंदू उप-धारा (1) के तहत अधिकार प्राप्त करती है, वह संदायादता स्वामित्व के तत्वों के साथ रखी जाएगी और किसी भी अन्य कानून के बावजूद, इसे वसीयत के माध्यम से भी हस्तांतरित किया जा सकता है।

(3) यदि कोई हिंदू हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 की शुरुआत के बाद मृतक होता है, तो उसकी संदायादता संपत्ति का हित वसीयत या अनुवांशिक उत्तराधिकार के माध्यम से इस अधिनियम के तहत स्थानांतरित होगा और उत्तरजीविता के आधार पर नहीं। संदायादता संपत्ति को ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि एक विभाजन हुआ है:

(a) बेटी को वही हिस्सा मिलेगा जो पुत्र को मिलता;

(b) पूर्व-निधन हो चुके पुत्र या पूर्व-निधन हो चुकी पुत्री का वह हिस्सा, जो उन्हें विभाजन के समय जीवित होने पर मिलता, उस पूर्व-निधन हो चुके पुत्र या पूर्व-निधन हो चुकी पुत्री के जीवित बच्चे को आवंटित किया जाएगा; और

(c) पूर्व-निधन हो चुके पुत्र या पूर्व-निधन हो चुकी पुत्री के पूर्व-निधन हो चुके बच्चे का वह हिस्सा, जो उसे विभाजन के समय जीवित होने पर मिलता, उस पूर्व-निधन हो चुके पुत्र या पूर्व-निधन हो चुकी पुत्री के बच्चे को आवंटित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

व्याख्या: इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, हिंदू मिताक्षरा सहपरिवार सदस्य का हित उस संपत्ति में उसका हिस्सा माना जाएगा, जो उसे तब मिलता यदि उसकी मृत्यु से ठीक पहले संपत्ति का विभाजन हुआ होता, चाहे वह विभाजन का दावा करने का हकदार था या नहीं।

(4) हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ के बाद, कोई भी न्यायालय पुत्र, पोते, या परपोते के खिलाफ उसके पिता, दादा, या परदादा से उधार ली गई किसी भी ऋण की वसूली के लिए केवल हिंदू कानून के तहत पवित्र दायित्व के आधार पर किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देगा, जो कि उक्त पुत्र, पोते या परपोते को उस ऋण का भुगतान करने की जिम्मेदारी देता है:

यह प्रदान किया जाता है कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले अनुबंधित किसी भी ऋण के मामले में, इस उपधारा में निहित कोई भी बात प्रभावित नहीं करेगी—

(a) किसी भी ऋणदाता के द्वारा पुत्र, पोते या परपोते के खिलाफ कार्यवाही करने के अधिकार; या

(b) किसी भी ऐसे ऋण की संबंध में या उसकी संतोषजनकता के लिए की गई किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण, और कोई भी ऐसा अधिकार या हस्तांतरण पवित्र दायित्व के नियम के तहत उसी प्रकार और उसी सीमा तक लागू होगा जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 को लागू नहीं किया गया होता।

व्याख्या - धारा (क) के उद्देश्य के लिए, "पुत्र", "पोता" या "परपोता" की अभिव्यक्ति को ऐसे पुत्र, पोते या परपोते के संदर्भ में माना जाएगा, जो हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से पहले जन्मा या गोद लिया गया हो।

(5) इस धारा में वर्णित कोई भी प्रावधान 20 दिसंबर 2004 से पहले संपन्न हुए विभाजन पर लागू नहीं होगा।

व्याख्या - इस धारा के उद्देश्यों के लिए, "विभाजन" का तात्पर्य किसी भी विभाजन से है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत सही ढंग से पंजीकृत विभाजन दस्तावेज द्वारा किया गया हो या न्यायालय के आदेश द्वारा किया गया विभाजन।

29. मुख्य मुद्दों की ओर लौटते हुए, विवाद यह है कि खाता संख्या 31, प्लॉट संख्या 1326, क्षेत्र 13 डेसिमल का भूमि रिकॉर्ड भदू महतो के नाम पर था, जिन्होंने अपने दो बेटों, बनेश्वर महतो और छठू महतो को छोड़ा। यह भी स्वीकार किया गया है

कि बनेश्वर महतो और छठू महतो ने अपनी भूमि का विभाजन किया और प्रत्येक को आधा हिस्सा दिया।

30. विवाद छठू महतो के हिस्से की 6 ½ डेसिमल भूमि से संबंधित है, जिनकी मृत्यु 1945 में हुई थी, और उनकी विधवा राशु महताइन और तीन पुत्र बिरबल महतो, हीरालाल महतो, मनीराम महतो और तीन पुत्रियाँ मन्जवा महताइन, संजवा महताइन और कुंती महताइन (याचिकाकर्ता/प्रतिवादी की माँ) थीं।

31. याचिकाकर्ता का कहना है कि छठू महतो की तीन बेटियाँ, मन्जवा महताइन, संजवा महताइन और कुंती महताइन ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की शुरुआत से पहले छठू महतो की मृत्यु के कारण कोई हिस्सा नहीं लिया। यह भी दावा किया गया है कि बिरबल महतो और हीरालाल महतो की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनकी संपत्ति का हिस्सा याचिकाकर्ता को एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी के रूप में हस्तांतरित किया गया।

32. यह भी स्वीकार किया गया है कि वर्तमान याचिकाकर्ता जगदीश महतो, कुंती महताइन के पुत्र, को याचिकाकर्ता के घर में पाला गया और अधिकांश समय वहां रहने की अनुमति दी गई।

33. पूरा मामला देखने के बाद, यह तय करने के लिए कि क्या सामान्य पूर्वज छठू महतो की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की शुरुआत से पहले यानी 17 जून 1956 या उसके बाद हुई, यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। यह स्वीकार किया गया है कि विवादित संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार का आवासीय घर है। यदि विवादित संपत्ति संदायादता संपत्ति मानी जाती है, तो भी धारा 6 के अनुसार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, बेटी को संदायादता में अधिकार नहीं मिलता था, इससे पहले के (संशोधित) अधिनियम 2005 से।

विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस (2020)9 SCC 1 में, यह निर्णय लिया गया कि यदि बेटी 09.09.2005 की तारीख को जीवित है, तो वह संशोधन अधिनियम की शुरुआत से संदायादता बन जाएगी। यह प्रावधान संशोधित धारा 6 बेटियों को जन्म के समय संदायादता का दर्जा प्रदान करता है, जैसा कि पुत्र को प्राप्त होता है, लेकिन उसे 09.09.2005 को जीवित रहना आवश्यक है। इस मामले में, याचिकाकर्ता की मां 1985 में मृत्यु हो गई थी।

34. चूंकि बेटी का सहपरिवार में अधिकार प्रतिस्थापित धारा 6 के तहत जन्म के आधार पर होता है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि पिता सहपरिवार सदस्य उस संशोधन की तिथि पर जीवित हो। बेटी अब 09.09.2005 से सहपरिवार सदस्य बन गई है और उस तिथि के बाद वह विभाजन का दावा कर सकती है, जो सहपरिवार की आवश्यक संरचना है। संशोधन की तिथि पर सहपरिवार की उपस्थिति जरूरी है ताकि बेटी सहपरिवार सदस्य के रूप में दिए गए अधिकारों का आनंद ले सके। यदि जीवित सहपरिवार सदस्य संशोधन की तिथि के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराधिकार जीवित सदस्य के माध्यम से नहीं बल्कि उत्तराधिकार या वसीयत द्वारा होता है जैसा कि प्रतिस्थापित धारा 6(3) में प्रदान किया गया है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि मिताक्षरा सहपरिवार के तहत सहपरिवार सदस्य का अधिकार कैसे प्राप्त होता है?

35. धारा 6 (संशोधन) अधिनियम 2005 के तहत बेटी पर दिए गए अधिकार की स्थिति उत्तराधिकार के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर नहीं है। मिताक्षरा सहपरिवार संपत्ति के उत्तराधिकार में उत्तरजीविता की विधि को 09.09.2005 से संशोधित धारा 6 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

36. इस प्रकरण में, यह प्रमाणित करने के लिए कि छातू महतो की मृत्यु वर्ष 1945 में हुई थी, याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड पर एक्सट.1 यानी मूल बिक्री कागज संख्या 6851 दिनांक 22.06.1950 प्रस्तुत किया है। इस बिक्री कागज में एक खरीदार श्री बीरू महतो हैं, जो स्व. छातू महतो के पुत्र हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि बीरू महतो वही बीरबल महतो हैं जो उनके भाई थे और उन्होंने *खातीयान*, किराया रसीद और मतदाता सूची की प्रमाणित प्रतियों पर भी भरोसा किया है।

37. ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय ट्रायल कोर्ट ने ऊपर दिए गए प्रमाण को अस्वीकार कर दिया है जिसमें दिखाया गया है कि छातू महतो (सामान्य पूर्वज) को उपरोक्त बिक्री कागज में वर्ष 1950 में मृत दिखाया गया है। यह निर्णय केवल इस आधार पर लिया गया कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत तर्क के आधार पर याचिकाकर्ता ने 30 वर्षीय दस्तावेज प्रस्तुत किया और बिक्री कागज की स्वामित्व की उचित व्याख्या नहीं की, बल्कि कहा कि यह उसके पिता के पास था और पिता की मृत्यु के बाद उसे प्राप्त हुआ। एक अनुमान लगाया गया कि जब पिता

स्वयं मृत थे, तो बिक्री कागज उनके पास कैसे था और इसे संदिग्ध दस्तावेज माना गया।

दूसरी ओर, उपरोक्त बिक्री कागज में छातू महतो के पुत्र बीरू महतो का नाम बीरबल महतो के स्थान पर उल्लेखित था। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उपरोक्त बिक्री कागज उसके पिता के पास उनके जीवनकाल में था, इससे पंजीकृत दस्तावेज की सामग्री को अविश्वसनीय मानने पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, छातू महतो की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में इस मामले के तथ्यात्मक पहलू के संदर्भ में कोई प्रभाव नहीं डालती है और यह उसके मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ।

38. माननीय ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया कि छातू महतो 1956 के बाद मृत हुए, केवल इस आधार पर कि छातू महतो की पत्नी का नाम 1970 की मतदाता सूची में था, जो प्रतिवादी द्वारा यह दावा किए जाने के साथ मेल खाता है कि वह वर्ष 1976-1977 में मृत हो गईं। इसलिए, माननीय ट्रायल कोर्ट द्वारा जीवित या मृत होने का जो अनुमान लगाया गया, वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 107 और 108 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। प्रतिवादी की ओर से उठाए गए तर्क के अनुसार पंजीकृत बिक्री कागज Ext.A पर संदेह व्यक्त किया गया, जो दर्शाता है कि छातू महतो की मृत्यु बिक्री कागज की तिथि 22.06.1950 को हुई थी और अन्य सामग्री पर चर्चा की गई, जो दोनों ट्रायल कोर्ट और अपीलीय कोर्ट द्वारा की गई थी।

39. यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की माँ, कांति देवी, का निधन लगभग 1985 में हुआ था, जब प्रतिवादी की उम्र 14 से 15 वर्ष थी। यह भी स्पष्ट है कि छातू महतो की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की शुरुआत से पहले हो गई थी। इस मामले में, प्रतिवादी की माँ, कांति देवी, जो छातू महतो की पुत्री हैं, को धारा 6 के तहत या संशोधन अधिनियम, 2005 के बाद, जो 09.09.2005 को लागू हुआ, संयुक्त परिवार संपत्ति का अधिकार कभी नहीं मिल सकता।

40. मूल धारा 6 में पुत्री को संयुक्त परिवार संपत्ति के उत्तराधिकार से बाहर रखा गया था क्योंकि उसे महिला वंशज होने के नाते संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती थी। इसके अलावा, इस मामले में विवादित संपत्ति

एक आवासीय घर है और आवासीय घर के संबंध में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 23 के तहत विशेष प्रावधान था जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

41. ***एमसी थिम्माराजू बनाम। पुट्टकेनचम्मा आकाशवाणी 1990 कर्नाटक, 317,*** के मामले में, कर्नाटका हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि "जब तक उपधारा द्वारा उत्पन्न अपेक्षा स्पष्ट रूप से किसी मामले को कवर नहीं करती, एक महिला उत्तराधिकारी, भले ही वह पुत्री हो, आवासीय घर में निवास का अधिकार नहीं रखेगी, यदि वह विवाहित है, जब तक यह साबित नहीं होता कि उसे उसके पति द्वारा त्याग दिया गया है या वह अलग हो गई है या वह विधवा हो गई है। जब अदालत के सामने कोई प्रमाण नहीं था कि याचिकाकर्ता किसी भी तरीके से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा के अंतर्गत आने के लिए योग्य थी, तो निचली अदालत ने उसे निवास का अधिकार देने में गलती की।"

42. इस तत्काल अपील में, ट्रायल कोर्ट और पहले अपीलीय कोर्ट के निर्णय की समीक्षा से <u>यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, जो संयुक्त परिवार संपत्ति का एकमात्र जीवित सदस्य है, ने अपने दो भाइयों की मृत्यु के बाद जीवित रहने के आधार पर संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त किया और याचिकाकर्ता की किसी भी बहन को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 की संशोधित धारा के लागू होने की तारीख यानी 09.09.2005 से कभी भी संयुक्त परिवार की स्थिति प्राप्त नहीं हुई।</u> मुकदमे में प्रतिवादी की स्थिति केवल अनुमति प्राप्त करने वाली है, बिना किसी वास्तविक अधिकार के।

43. इसके अनुसार, याचिकाकर्ता को मुकदमे की संपत्ति पर वैध अधिकार, शीर्षक और हित प्राप्त हुआ है और वह प्रतिवादी से मुकदमे की अनुसूचित बी संपत्ति की कब्जेदारी को पुनः प्राप्त करने का हकदार है।

44. इस अपील में उठाए गए महत्वपूर्ण कानूनी सवालों की रोशनी में पहले अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री की पूरी समीक्षा के बाद, मुझे पहले अपीलीय कोर्ट द्वारा पारित निर्णय में कोई भी अवैधता या दोष नहीं दिखाई देता, जिसे इस प्रकार से सही ठहराया और पुष्टि की जाती है।

45. इसके अतिरिक्त, मुझे अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई कानूनी सटीकता नहीं दिखाई देती और इस अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसे इस प्रकार से खारिज किया जाता है।

46. दोनों पक्ष अपने-अपने खर्चे खुद वहन करेंगे।

47. इस निर्णय की एक प्रति और ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड संबंधित कोर्ट को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

48. लंबित I.A. Nos. 2023 का 9493 और 203 का 3016 को इस प्रकार से निपटाया गया।

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जज)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 29/ 02 /2024
पप्पू-**NAFR/-**

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**